

STOP
STOP Trafficking and Oppression of children & women



रमोला भर चैरिटेबल ट्रस्ट

**मानव
तस्करी
पर पुस्तिका**



RAMOLA BHAR CHARITABLE TRUST (Regd.)

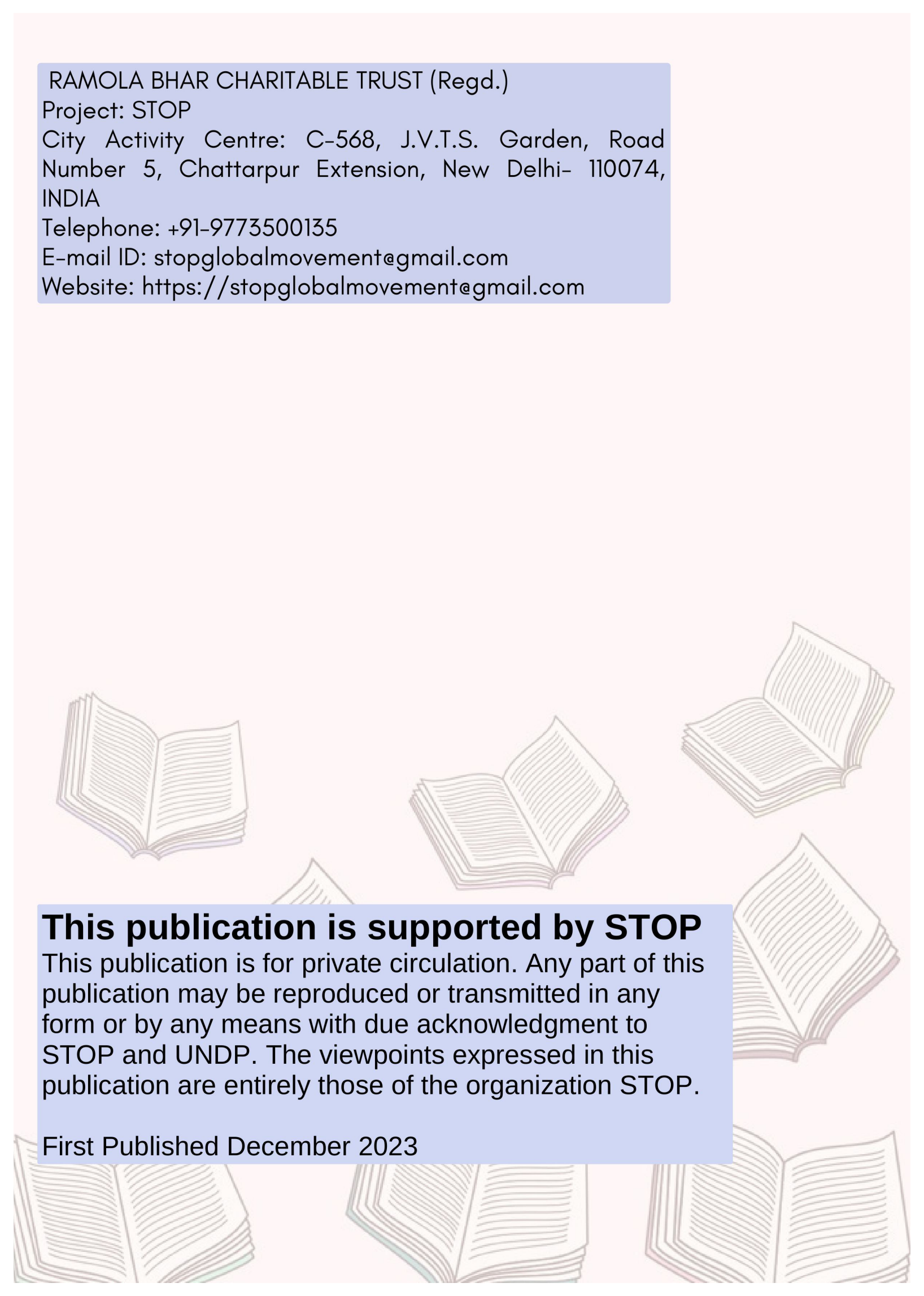
Project: STOP

City Activity Centre: C-568, J.V.T.S. Garden, Road
Number 5, Chattarpur Extension, New Delhi- 110074,
INDIA

Telephone: +91-9773500135

E-mail ID: stopglobalmovement@gmail.com

Website: <https://stopglobalmovement@gmail.com>



This publication is supported by STOP

This publication is for private circulation. Any part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means with due acknowledgment to STOP and UNDP. The viewpoints expressed in this publication are entirely those of the organization STOP.

First Published December 2023

पावती

बाल श्रम एक सामाजिक बुराई है जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग का शोषण करती है; बच्चे। 2020 की शुरुआत में लगभग 160 मिलियन बच्चे बाल श्रम के अधीन थे, जिसमें 9 मिलियन अतिरिक्त बच्चे COVID-19 के प्रभाव के कारण जोखिम में थे। बाल श्रम के परिणामस्वरूप अत्यधिक शारीरिक और मानसिक क्षति हो सकती है, और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है।

इससे गुलामी और यौन या आर्थिक शोषण हो सकता है। और लगभग हर मामले में, यह बच्चों को स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल से वंचित कर देता है, उनके मौलिक अधिकारों को सीमित कर देता है और उनके भविष्य को खतरे में डाल देता है। तस्करी के शिकार बच्चों को अक्सर हिंसा, दुर्व्यवहार और अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघन का शिकार होना पड़ता है। और कुछ को कानून तोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। लड़कियों के लिए, यौन शोषण का खतरा बड़ा होता है, जबकि लड़कों का सशस्त्र बलों या समूहों द्वारा शोषण किया जा सकता है। इस पुस्तिका के माध्यम से हमारा लक्ष्य बाल श्रम की कार्यप्रणाली, इसकी यथास्थिति और इससे निपटने के लिए जिम्मेदार कई कारकों का पता लगाना है।

सामग्री

- 1) मानव तस्करी क्या है?
- 2) मानव तस्करी के बारे में मिथक और तथ्य
- 3) भारत में मानव तस्करी की व्यापकता
- 4) मानव तस्करी प्रक्रिया के चरण
- 5) मानव तस्करी के कारण
- 6) आईपीसी के कानून और धाराएं
- 7) निष्कर्ष

**मानव तस्करी
क्या है?**

- यह इंसानों का अवैध व्यापार है. यह उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से लोगों को वित्तीय लाभ के लिए शोषणकारी स्थितियों में रखा जाता है। इसमें इंसानों की बिक्री, खरीद और कब्ज़ा शामिल है, और इसलिए, इसे 21वीं सदी में गुलामी का नया रूप माना जाता है। यह शोषण के माध्यम से महत्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दों में से एक बन गया है, जो न केवल एक देश के भीतर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है।

- इसमें किसी प्रकार का श्रम या वाणिज्यिक कार्य प्राप्त करने के लिए बल, धोखाधड़ी या जबरदस्ती का उपयोग शामिल है।

- इसमें न केवल यौन तस्करी शामिल है, बल्कि अन्य गतिविधियाँ भी शामिल हैं जिनमें शामिल हैं—
अंग व्यापार के लिए तस्करी, जबरन आपराधिक गतिविधियों के लिए तस्करी, जबरन आपराधिक गतिविधियों के लिए तस्करी श्रम, जिसे श्रम तस्करी भी कहा जाता है।

- इन गतिविधियों से शारीरिक स्वायत्तता और व्यक्तियों के आत्मनिर्णय का उल्लंघन होता है।

- मानव तस्करी की घटनाओं की उत्पत्ति प्राचीन है। प्राचीन भारत के साथ-साथ दुनिया के ऐतिहासिक आख्यान युद्धों के कारण मानव तस्करी के उदाहरणों से भरे हुए हैं और राज्यों के बीच युद्धों के कारण दास के रूप में उपयोग किए जाते हैं, और मुआवजे के हिस्से के रूप में भी, जो अक्सर विशेष रूप से, सामान्य तौर पर महिलाओं और दास का रूप ले लेता है, । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों ने इस पुरानी समस्या पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू किया जब 1940 के दशक के अंत में संयुक्त राष्ट्र में विभिन्न देशों ने एक संगठित तरीके से इस पर विचार-विमर्श शुरू किया। इस घृणित प्रथा पर अंतरराष्ट्रीय विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप "मानव तस्करी" शब्द को स्पष्ट किया गया और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया।

- चूँकि अपने सभी रूपों में मानव तस्करी मानव अधिकारों का सीधा अपमान था। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति के इस क्रॉस-कंट्री अपराध से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अपनाया, जिसे - ट्रांसनेशनल संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 2002 और इसके दो महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल के रूप में जाना जाता है। कन्वेंशन और प्रोटोकॉल का अनुमोदन करने के बाद, भारत ने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी इस खतरे के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का अपना दृढ़ संकल्प दिखाया।

मानव तस्करी के बारे में मिथक

आज के सबसे ग़लत समझे जाने वाले सामाजिक न्याय मुद्दों में से एक मानव तस्करी है। इसे मापना या पहचानना बेहद जटिल और अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है।

जनता की अनिश्चितता को और बढ़ाते हुए, फिल्मों, साहित्य और मीडिया के अन्य रूपों में मानव तस्करी को अक्सर विकृत किया जाता है। इस व्यापक ग़लतफ़हमी के आलोक में, हम मानव तस्करी से संबंधित 13 विशिष्ट (और असामान्य) झूठ प्रदान करते हैं।

मिथक 1- मानव तस्करी एक विदेशी समस्या है

तथ्य- मानव तस्करी दुनिया भर के लगभग हर देश में होती है, और इसकी सबसे अधिक संभावना वहीं होती है जहां आप रहते हैं।

मिथक 2- सभी तस्कर पुरुष हैं

तथ्य- यूएनओडीसी के अनुसार, अनुमानित 72% दोषी तस्कर पुरुष हैं, और 28% महिलाएं हैं।

मिथक 3- तस्करी की सभी पीड़ित महिलाएं हैं

तथ्य- यह सच है कि मानव तस्करी की शिकार अधिकांश महिलाएं हैं (पोलारिस के अनुसार 75%); हालाँकि, पुरुष और लड़के भी सेक्स और श्रम तस्करी से व्यापक रूप से प्रभावित होते हैं।

मिथक 4- मानव तस्करी केवल गरीब समुदायों में होती है

तथ्य- हर जाति, लिंग पहचान, उम्र और आर्थिक स्थिति के लोग श्रम और यौन तस्करी के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। असुरक्षा कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है, और गरीबी केवल एक ऐसी परिस्थिति है।



भारत में मानव तस्करी की व्यापकता

पुलिस ने 2021 में देश भर में एएचटीयू के तहत दर्ज 2,189 मामलों में से 84.7% में आरोप पत्र दायर किया।
केवल 16/% मामलों में ही सज़ा हुई।

एएचटीयू (मानव तस्करी विरोधी इकाई), एक एकीकृत टास्क फोर्स, 2007 में स्थापित की गई थी। यह बल केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वित्त पोषण के साथ, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों से कर्मियों को आकर्षित करता है।

a) रॉयटर्स के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में अनुमानित 20 मिलियन व्यावसायिक वेश्याओं में से 16 मिलियन महिलाएं और लड़कियां यौन तस्करी की शिकार हैं।

b) एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में मानव तस्करी के मामलों में सजा की दर लगातार कम बनी हुई है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी '2022 ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स' रिपोर्ट में कहा है कि भारत तस्करी के उन्मूलन के लिए न्यूनतम मानकों को पूरी तरह से पूरा नहीं करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में से 22 ने किसी भी बंधुआ मजदूरी पीड़ितों की पहचान करने या संबंधित नियमों के तहत कोई मामला दर्ज करने की सूचना नहीं दी, जबकि तस्करो के बरी होने की दर 89 प्रतिशत रही।

c) एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 में देश में हर दिन आठ बच्चों की तस्करी की गई और उनका शोषण किया गया।

d) एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 768 एएचटीयू कार्यात्मक हैं और 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने सभी जिलों में इन इकाइयों को स्थापित करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

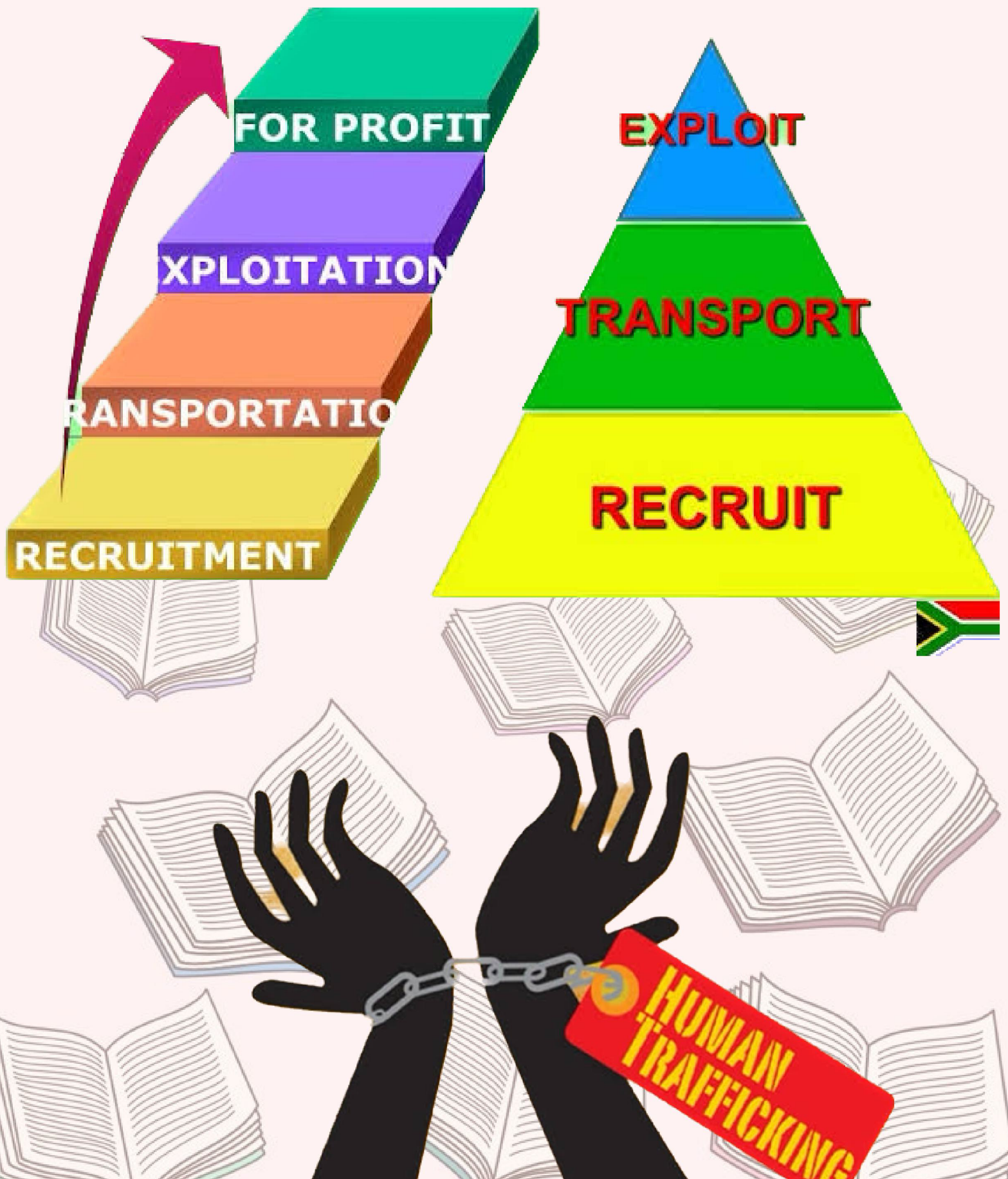
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार ने तस्करी के अपराधों में कथित संलिप्तता के लिए सरकारी अधिकारियों की जांच, मुकदमा चलाने या उन्हें दोषी ठहराने की रिपोर्ट नहीं की।

हाल ही में जारी रिपोर्ट में भी निराशा व्यक्त की गई है क्योंकि सरकार ने व्यक्तियों की तस्करी से निपटने या बल, धोखाधड़ी या जबरदस्ती की आवश्यकता को हटाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 370 में संशोधन करने के लिए अपनी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) में कोई अपडेट नहीं किया है। बाल यौन तस्करी साबित करें.



मानव तस्करी के चरण

मानव तस्करी की प्रक्रिया



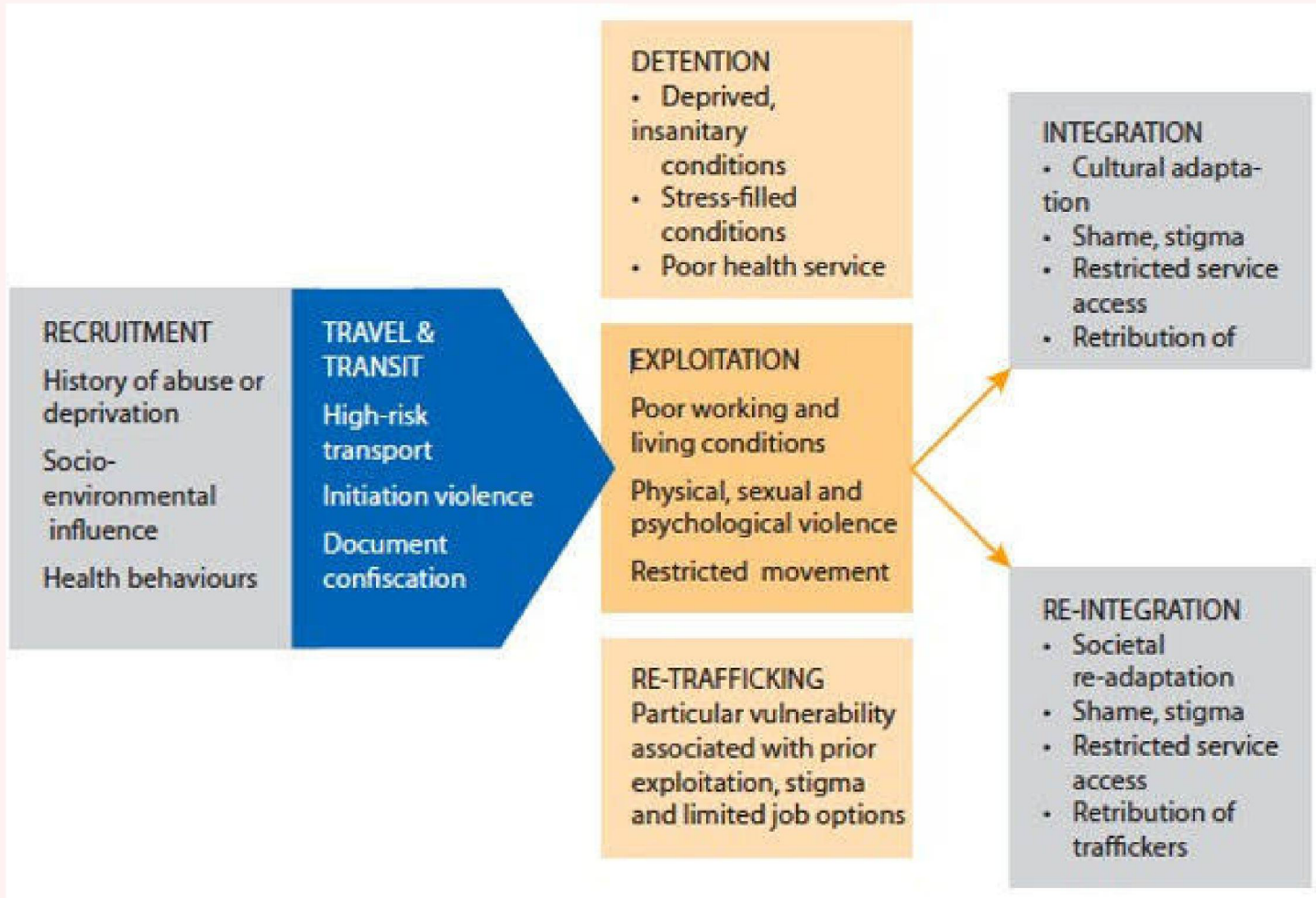
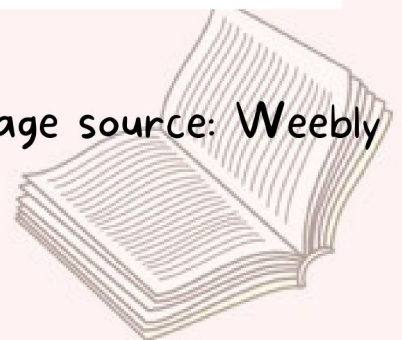


Image source: Weebly



मानव तस्करी के कारण

मानव तस्करी के मामलों में देखा जाने वाला सबसे आम पैटर्न "बेहतर जीवन" के लिए कम आय वाले क्षेत्रों से उच्च आय वाले क्षेत्रों की ओर जाना है।

बेहतर जीवन की व्यक्तिपरक अवधारणा ने मानव तस्करी के कई कारणों और कारणों को जन्म दिया है।

1) निर्धनता

माता-पिता अपने बच्चों को बेचते हैं।

गरीबी से छुटकारा पाने के लिए, और आर्थिक कठिनाइयों के बिना बेहतर जीवन जीने के लिए।

इससे दो बड़ी चुनौतियाँ पैदा हुई हैं, जिनमें शामिल हैं-

नतीजा

A] बाल श्रम

यह किसी भी प्रकार के काम के माध्यम से बच्चों के शोषण के लिए शब्द है जो उनका बचपन छीन लेता है, उन्हें नियमित स्कूल जाने से रोकता है, और उनके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए बुरा है।

b) बाल विवाह

18 वर्ष की आयु से पहले विवाह औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है। यह एक प्रकार की लिंग आधारित हिंसा है जो बच्चों से उनका बचपन छीन लेती है और उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है। इससे उनकी शिक्षा में भी बाधा आती है और दुर्व्यवहार, पूर्वाग्रह और हिंसा के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

2] सामाजिक-सांस्कृतिक आचरण

पितृसत्तात्मक मानसिकता के प्रचलन ने समाज में लड़कियों और महिलाओं के अवमूल्यन की संस्कृति पैदा कर दी है।

नतीजा

a] घरेलू हिंसा

किसी अंतरंग साथी पर शक्ति और नियंत्रण हासिल करने या बनाए रखने के लिए किसी भी रिश्ते में नियोजित व्यवहार के पैटर्न को घरेलू हिंसा या दुर्व्यवहार के रूप में जाना जाता है। दुर्व्यवहार को किसी अन्य व्यक्ति के प्रति जबरदस्ती, धमकी या हानिकारक शारीरिक, यौन, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक व्यवहार के रूप में परिभाषित किया गया है।

घरेलू हिंसा निम्नलिखित रूप ले सकती है-

- 1) वैवाहिक बलात्कार
- 2) पत्नियों की यौन आवश्यकताओं की उपेक्षा
- 3) पुत्र-पसंद के कारण एकाधिक गर्भधारण

पीड़ित सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण के रूप में बेहतर जीवन चाहते हैं, जिससे वे मानव तस्करी के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।

3] प्रवास

यह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आंदोलन को संदर्भित करता है - या तो एक देश के भीतर या राष्ट्रीय सीमाओं के पार।

कारण

गरीबी, मानवाधिकारों की कमी, सामाजिक या आर्थिक अवसर की कमी, संघर्ष या अस्थिरता से खतरे और इसी तरह की स्थितियाँ

तस्करों द्वारा इन कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है।

आईपी के कानून और धाराएँ

1) अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (PITA)

यह अधिनियम महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार और वेश्यावृत्ति को दबाने के लिए बनाया गया था।

कानून के अनुसार, वेश्यावृत्ति तब अपराध बन जाती है जब किसी व्यक्ति का व्यावसायिक शोषण किया जाता है।

यह वेश्यावृत्ति को अवैध नहीं बनाता है, लेकिन यह परिसर को वेश्यालय के रूप में रखने और उपयोग करने को बनाता है - वेश्यावृत्ति के माध्यम से अर्जित आय पर रहना, दलाली करना, याचना करना, किसी व्यक्ति को हिरासत में या अन्यथा वेश्यावृत्ति के लिए बहकाना और सार्वजनिक क्षेत्र में वेश्यावृत्ति करना।

यदि वेश्यावृत्ति स्वतंत्र रूप से या स्वेच्छा से की जाती है तो यह अपराध नहीं होगा।

निम्नलिखित इस कानून के प्रावधानों की रूपरेखा है जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से संबंधित है।

ए) अधिनियम बच्चे को ऐसे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

बी) अधिनियम के एस-5 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से किसी बच्चे को खरीदता है, प्रेरित करता है या ले जाता है तो कानून में निर्धारित सजा अधिकतम तीन साल की कैद है, जिसे प्रकृति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है।

ग) अधिनियम के प्रावधान के तहत, यदि किसी असंबंधित वयस्क व्यक्ति को रहस्यमय परिस्थितियों में किसी बच्चे की हिरासत में पाया जाता है, तो कानून ऐसी हिरासत को अधिनियम का उल्लंघन मानता है।

2) पॉक्सो अधिनियम, 2012 (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण)

याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु: यदि कोई व्यक्ति यौन इरादे से किसी बच्चे के पास गया है, तो उस व्यक्ति पर POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।

1] इसका उद्देश्य बच्चों को सभी प्रकार के यौन शोषण से बचाना है। इसे बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने और ऐसे अपराधों और संबंधित घटनाओं की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया है।

2] अधिनियम एक बच्चे को अठारह वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है।

3] जो लोग यौन उद्देश्यों के लिए बच्चों की तस्करी करते हैं, वे भी अधिनियम में उकसावे से संबंधित प्रावधानों के तहत दंडनीय हैं।

4] जो लोग यौन उद्देश्यों के लिए बच्चों की तस्करी करते हैं, वे भी अधिनियम में उकसावे से संबंधित प्रावधानों के तहत दंडनीय हैं।

5] कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए झूठी शिकायत करने पर सजा का प्रावधान किया गया है।

6] विशेष अदालत की अनुमति के बिना मीडिया को बच्चे की पहचान उजागर करने से रोक दिया गया है।

3] किशोर न्याय अधिनियम 2015

अधिनियम 16-18 वर्ष के आयु वर्ग के उन किशोरों पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति देता है जो कानून के उल्लंघन में पाए गए हों, विशेषकर जघन्य अपराधों में।

यह प्रावधान करता है-

- 1) अनाथ, परित्यक्त और आत्मसमर्पण किए गए बच्चों जैसी कई परिभाषाओं का समावेश। यह गोद लेने के प्रावधान निर्धारित करता है।
- 2) अधिनियम हर जिले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों की स्थापना का आदेश देता है। दोनों में कम से कम एक-एक महिला सदस्य होनी चाहिए।
- 3) यह बाल देखभाल संस्थानों के अनिवार्य पंजीकरण को भी अनिवार्य बनाता है।
- 4) इसमें बच्चों के खिलाफ किए गए नए अपराध भी शामिल हैं जैसे अवैध गोद लेने, बाल देखभाल संस्थानों में शारीरिक दंड और विकलांग बच्चों के खिलाफ अपराध सहित किसी भी उद्देश्य के लिए बच्चों की बिक्री और खरीद।

महत्वपूर्ण बिंदु

POCSO अधिनियम बाल अपराधियों और वयस्क अपराधियों से जुड़े मामलों पर लागू होता है जबकि JJ अधिनियम बाल अपराधियों और वयस्क उत्तरजीवियों से जुड़े मामलों पर लागू होता है।

केंद्र सरकार की योजनाएँ

- उज्ज्वला: तस्करी की रोकथाम और तस्करी तथा वाणिज्यिक यौन शोषण के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए एक व्यापक योजना।
- वन स्टॉप सेंटर योजना
- महिला छात्रावास योजना
- महिला हेल्प लाइन योजना
- स्वाधार गृह (मुश्किल परिस्थितियों में महिलाओं के लिए एक योजना)
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- देशभर के 10,000 पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित हैं
- महिला पुलिस स्वयंसेवक
- पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना

निष्कर्ष

"मानव तस्करी" शब्द अत्यधिक जटिल और व्यापक लग सकता है लेकिन इसमें हमारे चारों ओर होने वाले विभिन्न प्रकार के अपराध शामिल हैं। इस अपराध को घटित होने से रोकने के लिए, हमें वेश्यालयों से जाकर पीड़ितों को बचाने की आवश्यकता नहीं है; हमें बस अपने परिवेश के प्रति अधिक जागरूक होकर इसकी रोकथाम में योगदान देने की आवश्यकता है। हमें यह समझना चाहिए कि मानव तस्करी का अगला शिकार कोई भी हो सकता है, यहां तक कि आप और आपके परिवार का कोई सदस्य भी। अकेले कानून इस खतरे से निपटने में मदद नहीं कर पाएंगे; हम सभी को केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य नामित अधिकारियों के साथ अपने चारों ओर एक स्वस्थ और सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने की जिम्मेदारी साझा करनी चाहिए।

